राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डी.बी. आपराधिक अपील संख्या 720/2002

राज्य

----अपीलकर्ता

बनाम

रामदीन और अन्य

----प्रतिवादी

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री सी.एस. ओझा

प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्री बी.एस. राठौर

माननीय डॉ. न्यायमूर्ति पुष्पेन्द्र सिंह भाटी

माननीय श्रीमान. जस्टिस मदन गोपाल व्यास

प्रलय

रिपोर्ट योग्य

16/10/2024 को आरक्षित

05/12/2024 को घोषित

प्रति डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी, जे:

1. यह आपराधिक अपील दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 के तहत अपीलकर्ता-राज्य द्वारा दिनांक 11.04.2002 के बरी करने के फैसले को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसमें उक्त राहत का दावा किया गया है:

> *"इसलिए, यह बहुत सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि कृपया अपील की अनुमति दी जाए, अपील की अनुमति दी जाए, दिनांक 11.04.2002 के आरोपित निर्णय को कृपया रद्द किया जाए और अलग रखा जाए और आरोपी प्रति*

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

वादियों को धारा 498-ए, 201 और 304-बी और वैकल्पिक रूप से धारा 302/34 आईपीसी के तहत अपराध के लिए दंडित किया जाए।"

2. मामला वर्ष 2001 में घटित एक घटना से संबंधित है और वर्तमान अपील वर्ष 2002 से लंबित है।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य, जैसा कि अपीलकर्ता-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रखा गया है, वे हैं कि 03.10.2001 को भोपालगढ़ पुलिस स्टेशन में पीडब्लू.17 रामस्वरूप द्वारा एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी छोटी बहन कौशल्या (मृतक) की शादी 3 साल पहले राजूराम, पुत्र रामदीन (यहां अभियुक्त-प्रतिवादी) से हुई थी और उक्त विवाह में सामाजिक स्थिति और मानक के अनुसार दहेज दिया गया था। मृतका ने अपने परिवार को दहेज की मांग और पिछले 7-8 महीनों से उसके ससुर और सास द्वारा इस बहाने से लगातार परेशान किए जाने के बारे में बताया कि उसके परिवार ने शादी के समय पर्याप्त दहेज नहीं दिया था। सूचित किए जाने पर, उसके भाई (पीडब्लू-17) और उसकी मां, श्रीमती भंवरी (पीडब्लू-15) ने उसे सलाह दी कि वह अपने पिता के पोस्टिंग से लौटने का इंतजार करे

3.1. यह भी कहा गया कि मृतका के ससुर अर्थात रामदीन बलुंदा की रस्म से कुछ दिन पहले उनसे मिलने आए थे, जहां मृतका के माता-पिता ने अभियुक्त रामदीन से अनुरोध किया कि वे उसे परेशान न करें और उक्त रस्म में उनकी मांगें पूरी कर दी जाएंगी; परिणामस्वरूप, मृतका के परिवार ने 2.25 *तोला*सोना, एक टेलीविजन, 10 *तोला*उक्त अनुष्ठान में चांदी के आभूषणों के साथ अन्य सामान भी शामिल थे। हालाँकि, 03.10.2001 की सुबह लगभग 7-8 बजे, मृतका के परिवार को सूचित किया गया कि

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

पिछले दिन यानी 02.10.2001 को, आरोपी रामदीन (ससुर) और विद्यादेवी (सास) ने अपनी बहू कौशल्या की हत्या कर दी और सबूत नष्ट करने के लिए जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया।

3.2. उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304-बी, 498-ए एवं 201 के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कर तद्नुसार अनुसंधान प्रारम्भ किया गया, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण रामदीन एवं विद्यादेवी को गिरफ्तार किया गया, घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, गवाहों के बयान दर्ज किये गये, घटनास्थल से जले हुए कपड़े, मिट्टी एवं प्लास्टिक कंटेनर जब्त किये गये, घटनास्थल की फोटोग्राफी की गयी, दहेज में प्राप्त वस्तुओं की सूची तैयार की गयी तथा मृतका के दाह संस्कार में सम्मिलित व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया गया, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

3.3. आवश्यक जांच के बाद, 05.01.2002 को आरोपी रामदीन और विद्यादेवी के खिलाफ धारा 498-ए, 304-बी और 201 आईपीसी के तहत और आरोपी सहीराम, गुलाब सिंह, हिंदूराम, भगवानगिरी और ओमप्रकाश के खिलाफ धारा 201 आईपीसी के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाड़ सिटी की अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया, जहां से मामला सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया और उसके बाद एडीजे, फास्ट ट्रैक, जोधपुर की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।

3.4. विद्वान ट्रायल कोर्ट ने आरोपी प्रतिवादी रामदीन और विद्यादेवी के खिलाफ धारा 498-ए और 304-बी आईपीसी के तहत आरोप तय किए और वैकल्पिक रूप से धारा 302/34 और 201 आईपीसी के तहत आरोप पढ़कर सुनाए गए और आरोपी प्रति वादियों को

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

समझाया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उचित सुनवाई का दावा किया और तदनुसार ट्रायल शुरू हुआ।

3.5. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपनी ओर से 19 गवाह पेश किए और बचाव पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में 3 गवाह पेश किए, जिसके बाद आरोपी-प्रति वादियों की सीआरपीसी की धारा 313 के तहत जांच की गई, जिसमें उन्होंने निर्दोष होने और संबंधित आपराधिक मामले में खुद को झूठा फंसाए जाने की दलील दी।

3.6. तत्पश्चात, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने तथा अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री और साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने, दिनांक 11.04.2002 के आक्षेपित निर्णय के तहत, अभियुक्त-प्रति वादियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, जिसके विरुद्ध अपीलकर्ता-राज्य द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गई है।

4. अपीलार्थी-राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सी.एस. ओझा ने प्रस्तुत किया कि ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग और उसके परिणामस्वरूप हुई मृत्यु के संबंध में अभियोजन पक्ष की कहानी पीडब्लू-13, पीडब्लू-14, पीडब्लू-15 और पीडब्लू-16 की गवाही से पुष्ट होती है, जो दहेज मृत्यु की घटना की पुष्टि करती है।

4.1 विद्वान वकील ने आगे दलील दी कि आरोपी-प्रति वादियों द्वारा विचाराधीन अपराध के बाद, मृतक का अंतिम संस्कार और अंतिम संस्कार जल्दबाजी में किया गया, यहां तक कि मृतक के परिवार के सदस्यों को भी सूचित नहीं किया गया, जिससे उनके (आरोपी-प्रति वादियों के) आचरण पर संदेह पैदा होता है और इस तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के आधार पर इसे साबित करने का दायित्व उन पर आता है।

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

5. दूसरी ओर, अपीलकर्ता-राज्य की ओर से प्रस्तुत दलीलों का विरोध करते हुए, अभियुक्त-प्रति वादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एस. राठौर ने दलील दी कि प्राथमिकी में न तो मृतका की मृत्यु से ठीक पहले उसके साथ किसी प्रकार की क्रूरता के तथ्य को उजागर किया गया है, न ही दहेज के बारे में कोई उल्लेख है। मृतका की मृत्यु से ठीक पहले किसी भी प्रकार की मांग न होने का तथ्य, इसे साबित करने के लिए किसी भी अन्य साक्ष्य के अभाव में और भी पुष्ट होता है, जिससे यह मामला वर्तमान मामले में आरोपों के दायरे से बाहर हो जाता है।

5.1 विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि अभियुक्त प्रति वादियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपने बयानों में, मुकदमे के दौरान लगाए गए आरोपों और उनके खिलाफ प्रस्तुत साक्ष्यों के बारे में पूर्ण स्पष्टीकरण दिया है।

5.2. विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि मृतका ने अपने परिवार के सदस्यों को दहेज की कथित मांगों के बारे में बहुत पहले ही सूचित कर दिया था और उसके बाद वह अपनी मृत्यु तक अपने मायके नहीं गई, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह उत्पन्न होता है कि उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की मांग की गई थी।

5.3. विद्वान वकील ने आगे कहा कि हत्या या अप्राकृतिक मृत्यु के तथ्य को साबित करने के लिए कोई चिकित्सा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे मामला आरोपी प्रति वादियों के पक्ष में झुक जाता है।

6. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

7. यह न्यायालय देखता है कि अभियुक्त-प्रति वादियों पर अपनी बहू की हत्या के अपराध का आरोप लगाया गया था, क्योंकि उसके परिवार ने दहेज की उनकी मांगों को पूरा करने में विफलता दिखाई थी, और मुकदमे के संचालन के बाद, विद्वान ट्रायल कोर्ट ने उन्हें संदेह का लाभ देते हुए, उन्हें धारा 304 बी, 498 ए, 302/34 और 201 आईपीसी के तहत आरोपों से बरी कर दिया, जो कि आरोपित निर्णय के तहत है।

8. यह न्यायालय यह मानता है कि, अनादि काल से भारतीय समाज सदियों पुराने श्लोक में निहित मूल्यों का पालन करता रहा है और उन्हें संजोता रहा है:

"यत्र नार्यस्तुपूज्यन्ते रमन्तेतत्र देवता:।"

उपर्युक्त संस्कृत श्लोक का अनुवाद है: "जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, वहाँ देवता प्रसन्न होते हैं।" यह श्लोक स्त्रियों के सम्मान और महत्व के महत्व पर प्रकाश डालता है, तथा इस बात पर बल देता है कि उनका सम्मान समग्र रूप से समाज की भलाई से जुड़ा हुआ है।

8.1. हालाँकि, राजस्थान के सांस्कृतिक रूप से समृद्ध ताने-बाने में, दहेज हत्याओं का कपटी साया मंडरा रहा है, जो महिलाओं की गरिमा और स्वायत्तता पर कलंक लगा रहा है। दहेज की घृणित प्रथा दुल्हनों के मूल्य को केवल एक वस्तु तक सीमित कर देती है, जिसका मूल्यांकन केवल विवाह में लाए गए मौद्रिक उपहारों से होता है। जहाँ एक ओर परिवार सामाजिक दबावों और प्रतिष्ठा की निरंतर चाहत से जूझ रहे हैं, वहीं कई युवतियाँ खुद को हिंसा और जबरदस्ती के जाल में फँसा पाती हैं, जिससे दुखद रूप से उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। इस तरह के जघन्य कृत्य न केवल अनगिनत बेटियों की मंद होती आशाओं

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

को बुझा देते हैं, बल्कि स्त्री-द्वेष के एक ऐसे चक्र को भी बढ़ावा देते हैं जो उनके अस्तित्व का ही अवमूल्यन करता है। तत्काल सामाजिक परिवर्तन और कड़े कानूनी उपायों की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि राजस्थान में - और वास्तव में, पूरे भारत में - महिलाओं की गरिमा ऐसे पुरातन मानदंडों के उन्मूलन पर निर्भर करती है।

9. इस समय यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामले में पारित निर्णय के प्रति सचेत है।***छबी करमाकर एवं अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (आपराधिक अपील संख्या 1556/2013)***, 29 अगस्त 2024 को तय), जिसमें माननीय न्यायालय ने धारा 304-बी आईपीसी के तहत अपराध के आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डाला है और उक्त निर्णय के प्रासंगिक अंश निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:

> *"राजिंदर सिंह (सुप्रा) के पैराग्राफ 9 में, इस न्यायालय ने आईपीसी की धारा 304 बी के अवयवों पर इस प्रकार चर्चा की थी:*
>
> *9. भारतीय दंड संहिता की धारा 304-बी के अंतर्गत अपराध के तत्वों को कई निर्णयों में बताया और दोहराया गया है। ऐसे चार तत्व हैं और वे इस प्रकार हैं:*
> *(क) महिला की मृत्यु किसी जलने या शारीरिक चोट के कारण हुई हो या उसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अलावा किसी अन्य कारण से हुई हो;*
> *(ख) ऐसी मृत्यु उसके विवाह के सात वर्ष के भीतर हुई हो;*
> *(ग) उसकी मृत्यु से ठीक पहले, उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा उसके साथ क्रूरता या उत्पीड़न किया गया हो; और*

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

(घ) ऐसी क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के संबंध में होना चाहिए।"

10. यह न्यायालय मानता है कि यह मामला भी एक ज्वलंत उदाहरण है जो इस विकासशील देश में दहेज हत्याओं के अस्तित्व के तथ्य को उजागर करता है। वर्तमान मामले में, विद्वान ट्रायल जज ने गवाहों पीडब्लू-13, पीडब्लू-14, पीडब्लू-15, पीडब्लू-16 और पीडब्लू-17 की गवाही और साथ ही उसकी मृत्यु से ठीक पहले दहेज की विशिष्ट माँग के बारे में अभियोजन पक्ष की कहानी पर विश्वास नहीं किया और इस प्रकार अभियुक्त-प्रति वादियों को संदेह का लाभ देते हुए, आक्षेपित निर्णय के तहत बरी कर दिया।

11. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने विचाराधीन निर्णय में यह उल्लेखनीय तथ्य माना है कि पीड़िता का दाह संस्कार, संबंधित अपराध की रिपोर्ट पुलिस को प्रस्तुत किए जाने से बहुत पहले ही कर दिया गया था। परिणामस्वरूप, जाँच के समय उसका शव उपलब्ध नहीं था, इसलिए उसकी जाँच नहीं की जा सकी।

11.1. यह न्यायालय यह भी मानता है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोगी-13 (कमला), अभियोगी-14 (बया), अभियोगी-15 (भंवरी), अभियोगी-16 (श्रवण), अभियोगी-17 (रामस्वरूप), वंदना-1 (सगतराम), वंदना-2 (बाबूदेवी) और वंदना-3 (सूरजाराम) की गवाही से यह सिद्ध हो गया है कि पीड़िता की मृत्यु उसके विवाह के तीन वर्ष बाद जलने के कारण हुई थी। अतः,**पहले और दूसरे घटक को संतुष्ट करता है**धारा 304-बी के तहत अपराध की, अर्थात् पीड़िता की मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अलावा जलने से हुई थी और उसकी शादी के 7 साल के भीतर हुई थी।

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

11.2. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि प्र.पी-5 (दिनांक 03.10.2001 की रिपोर्ट) से यह स्पष्ट है कि पीड़िता को पिछले 7-8 महीनों से उसके सास-ससुर द्वारा दहेज की मांग के संबंध में ताने और प्रताड़ित किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप, मृतका के परिवार द्वारा बलुंडा की रस्म के दौरान 2.25 लाख रुपये देकर दहेज की कुछ माँगें भी पूरी की गईं।तोलासोना, एक टेलीविजन, 10 तोलाचांदी के आभूषणों के साथ अन्य सामान।

11.3. यह न्यायालय यह भी देखता है कि बलुंडा अनुष्ठान के बाद, रक्षा बंधन उत्सव के दौरान भी, मृतक-पीड़िता ने अपने मायके जाने पर अपने माता-पिता को अपने ससुराल वालों द्वारा दहेज की अतिरिक्त मांगों के बारे में बताया। दहेज की अतिरिक्त मांग के इस तथ्य की पुष्टि पीडब्लू-14 (बया) की गवाही से भी होती है, जिसने कहा कि मृतक-पीड़िता ने रक्षा बंधन उत्सव के दौरान अपने आगमन पर, उसे अपने ससुर द्वारा दहेज की अपर्याप्त मात्रा के बारे में दिखाई गई निराशा के बारे में बताया, अर्थात, दिया गया सोना और चांदी बहुत कम था और वे उसे मार देंगे। पीडब्लू-15 की गवाही से भी इसकी पुष्टि होती है, जिसने कहा कि ससुराल वाले मृतका को फिर से उसी तरह परेशान कर रहे थे।

11.3.1. यह न्यायालय यह मानता है कि उपर्युक्त तथ्यात्मक ढाँचे और संबंधित अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही के आलोक में, यह स्पष्ट है कि पीड़िता को अभियुक्तों-प्रति वादियों द्वारा लगातार दहेज की माँग और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा ताकि वह अपनी अवैध माँग पूरी कर सके। अतः, विद्वान निचली अदालत को केवल उनके बयानों में सटीकता के अभाव के कारण संबंधित अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही में अनुचित त्रुटियाँ ढूँढने में अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए था। उपर्युक्त के आलोक

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

में,**धारा 304-बी का चौथा आवश्यक घटक**यह भी संतुष्ट है कि, इस प्रकार की गई क्रूरता या उत्पीड़न दहेज की मांग के संबंध में था।

11.4. यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि इस मामले में धारा 304-बी का अंतिम घटक यह है:

> *"(सी) **अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले**, उसे अपने पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा होगा;"*

11.4.1. यह न्यायालय इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से भी अवगत है।**सतबीर सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य,*(आपराधिक अपील संख्या 1735-1736 वर्ष 2010,28.05.2021 को निर्णय लिया गया)*** प्रासंगिक पैराग्राफ जिनमें "उसकी मृत्यु से ठीक पहले" शब्द की व्याख्या निम्नानुसार की गई है:

> *"के मामले में**कंस राज बनाम पंजाब राज्य, (2000) 5 एससीसी 207**, जिसमें तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि: "15. ... "शीघ्र पूर्व" <u>एक सापेक्ष शब्द है जिस पर प्रत्येक मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में विचार किया जाना आवश्यक है और कोई समय सीमा निर्धारित करके कोई कठोर सूत्र निर्धारित नहीं किया जा सकता।</u> ... दहेज हत्याओं के संबंध में, मृतक के प्रति क्रूरता या उत्पीड़न के अस्तित्व को दर्शाने वाली परिस्थितियाँ किसी विशेष उदाहरण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि सामान्यतः आचरण के एक क्रम को संदर्भित करती हैं। ऐसा आचरण एक समयावधि में फैला हो सकता है।**<u>दहेज की मांग पर आधारित क्रूरता के प्रभाव और परिणामी मृत्यु के बीच निकटतम और जीवंत संबंध को अभियोजन पक्ष द्वारा साबित किया जाना आवश्यक है</u>**।दहेज की मांग, ऐसी मांग और मृत्यु की तारीख के आधार पर क्रूरता या*

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

> *उत्पीड़न का समय बहुत दूर नहीं होना चाहिए, जिसे परिस्थितियों के अनुसार काफी पुराना माना जाए।*
>
> *इसलिए, अदालतों को यह निर्धारित करने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या क्रूरता या उत्पीड़न और पीड़ित की मृत्यु के बीच की अवधि "कुछ समय पहले" की श्रेणी में आती है। उपरोक्त निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि **"निकटतम और लाइव लिंक"** क्रूरता और पीड़ित की परिणामी मृत्यु के बीच।"*

11.4.2. यह न्यायालय देखता है कि वर्तमान मामले में, रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य और ऊपर जांचे गए गवाहों की गवाही से, यह स्पष्ट है कि पीड़िता को दहेज की मांग के चलते परेशान किया जा रहा था और बलुंडा अनुष्ठान के दौरान ऐसी गैरकानूनी मांगों की पूर्ति के बाद भी यह जारी रहा। पीड़िता ने रक्षा बंधन के दौरान आखिरी बार अपने परिवार से मुलाकात की और दहेज की मांग के कारण हो रहे उत्पीड़न के बारे में अपने परिवार को सूचित किया। भले ही यह मौत के वास्तविक कारण से 2 महीने पहले हुआ हो, लेकिन यह इतना लंबा समय नहीं है कि दावे को बेकार कर दिया जाए, खासकर ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग को लेकर लंबे समय तक क्रूरता के पिछले उदाहरणों के मद्देनजर, जो प्रकृति में निरंतर था, जिससे क्रूरता और पीड़िता की परिणामी मृत्यु के बीच एक "निकटतम और जीवंत संबंध" स्थापित होता है।

12. यह न्यायालय यह भी मानता है कि वर्तमान मामले में, विचाराधीन अपराध पीड़िता के वैवाहिक घर की चारदीवारी के भीतर हुआ था और इसलिए, ऐसी परिस्थिति में, भारतीय

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के आधार पर, तथ्यों और उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने का भार ससुराल वालों पर है, जो घर में मौजूद थे।

12.1 यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामले में दिए गए निर्णय से भी अवगत है।***बलवीर सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य, (आपराधिक अपील संख्या 301/2015)***, *6 अक्टूबर, 2023 को निर्णय लिया गया)*,जिसके प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

> *"साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 की प्रयोज्यता को नियंत्रित करने वाले कानून के सिद्धांत*
>
> *33. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में निम्नानुसार कहा गया है:*
>
> *"106. विशेष रूप से ज्ञान के भीतर तथ्य को साबित करने का भार - जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है।"*
>
> *34. साक्ष्य अधिनियम की धारा 106, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, यह उपबंध करती है कि जब कोई तथ्य किसी व्यक्ति के विशेष ज्ञान में हो, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा। शब्द "**विशेष रूप से**" का अर्थ है ऐसे तथ्य जो अभियुक्त के ज्ञान में सर्वोपरि या अपवादस्वरूप हों। आपराधिक मुकदमों में लागू होने वाला सामान्य नियम कि अभियुक्त के अपराध को सिद्ध करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में निहित तथ्यों के नियम द्वारा किसी भी प्रकार संशोधित नहीं होता है।**साक्ष्य अधिनियम की धारा 106, साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 का अपवाद है।**धारा 101 अपने उदाहरण (क) के साथ यह सामान्य नियम निर्धारित करती है कि किसी आपराधिक मामले में सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर होता है*

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

और धारा 106 का उद्देश्य उसे इस दायित्व से मुक्त करना बिल्कुल नहीं है। इसके विपरीत, यहकुछ असाधारण मामलों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें अभियोजन पक्ष के लिए उन तथ्यों को स्थापित करना असंभव या किसी भी दर पर अनुपातहीन रूप से कठिन होगा, जो "विशेष रूप से अभियुक्त के ज्ञान में हैं और जिन्हें वह बिना किसी कठिनाई या असुविधा के साबित कर सकता है"।

35. शंभू नाथ मेहरा बनाम अजमेर राज्य, एआईआर 1956 एससी 404 में, इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में प्रयुक्त शब्द "विशेष रूप से" पर विचार करते हुए कहा कि ***विवियन बोस, जे.,****निम्नानुसार देखा गया:*

*"11. ... शब्द "विशेष रूप से" इस बात पर जोर देता है।****इसका अर्थ है ऐसे तथ्य जो सर्वोपरि या असाधारण रूप से उसके ज्ञान में हों।*** *यदि इस धारा की व्याख्या अन्यथा की जाए, तो यह बेहद चौंकाने वाला निष्कर्ष निकलेगा कि हत्या के मामले में यह साबित करने का दायित्व अभियुक्त पर है कि उसने हत्या नहीं की है, क्योंकि उससे बेहतर कौन जान सकता है कि उसने हत्या की है या नहीं। यह स्पष्ट है कि यह उद्देश्य नहीं हो सकता और प्रिवी काउंसिल ने दो बार इस धारा की व्याख्या करने से इनकार कर दिया है, जैसा कि भारत के बाहर कुछ अन्य अधिनियमों में पुनरुत्पादित किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि अभियुक्त पर यह साबित करने का दायित्व है कि उसने वह अपराध नहीं किया है जिसके लिए उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है।*

36. शंभू नाथ (सुप्रा) के उपर्युक्त निर्णय का उल्लेख किया गया है और उस पर भरोसा किया गया है ***नागेंद्र साह बनाम बिहार राज्य,***

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

***(2021) 10 एस.सी.सी 725**, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:*

22. इस प्रकार, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 उन मामलों पर लागू होगी जहाँ अभियोजन पक्ष उन तथ्यों को स्थापित करने में सफल रहा है जिनसे अभियुक्त के विशेष ज्ञान में मौजूद कुछ अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जबयदि अभियुक्त उक्त अन्य तथ्यों के अस्तित्व के बारे में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो न्यायालय हमेशा उचित निष्कर्ष निकाल सकता है।

23. जब कोई मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित हो, यदि अभियुक्त साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के आधार पर उस पर लगाए गए भार के निर्वहन में उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहता है, तो ऐसी विफलता परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी प्रदान कर सकती है। साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114 के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त स्थिति और भी सुदृढ़ हो जाती है। यह न्यायालय को किसी भी ऐसे तथ्य के अस्तित्व की उपधारणा करने का अधिकार प्रदान करती है जिसके घटित होने की संभावना उसके विचार में हो। इस प्रक्रिया में, न्यायालयों को मामले के तथ्यों के अतिरिक्त प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण आदि के सामान्य क्रम को भी ध्यान में रखना होगा। इन परिस्थितियों में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 में निहित सिद्धांतों का भी उपयोग किया जा सकता है।

38. त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2006) 10 एससीसी 681 में, यह न्यायालय घर के भीतर हुई हत्या के एक ऐसे ही मामले पर विचार कर रहा था। वर्तमान मामले के तथ्यों में निम्नलिखित टिप्पणियाँ प्रासंगिक मानी जाती हैं:

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

*"14. यदि कोई अपराध किसी घर की गोपनीयता के अंदर और ऐसी परिस्थितियों में होता है, जहां हमलावरों को उस समय और अपनी पसंद की परिस्थितियों में अपराध की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का पूरा अवसर मिलता है, तो अभियोजन पक्ष के लिए अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करना बेहद मुश्किल होगा, यदि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के सख्त सिद्धांत पर, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अदालतों द्वारा जोर दिया जाता है।***एक न्यायाधीश किसी आपराधिक मुकदमे की अध्यक्षता सिर्फ़ यह देखने के लिए नहीं करता कि किसी निर्दोष को सज़ा न मिले। एक न्यायाधीश यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई दोषी बच न पाए। दोनों ही सार्वजनिक कर्तव्य हैं।***(देखें स्टरलैंड बनाम लोक अभियोजन निदेशक [[1944] ए.सी. 315: [1944] 2 ऑल ईआर 13 (एचएल)] - पंजाब राज्य बनाम करनैल सिंह [(2003) 11 एससीसी 271: 2004 एससीसी (क्रि) 135] में जे. अरिजीत पसायत द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत।)***कानून अभियोजन पक्ष पर ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई दायित्व नहीं डालता जो प्रस्तुत करना लगभग असंभव हो या किसी भी स्थिति में अत्यंत कठिन हो। अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करे जिन्हें प्रस्तुत करने में वह सक्षम हो।***

*15. जहां हत्या जैसा अपराध किसी घर के अंदर गुप्त रूप से किया जाता है, तो मामले को स्थापित करने का प्रारंभिक भार निस्संदेह अभियोजन पक्ष पर होगा, लेकिन आरोप को स्थापित करने के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मात्रा उसी स्तर की नहीं हो सकती है जैसी परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अन्य मामलों में आवश्यक होती है।****यह भार अपेक्षाकृत हल्का होगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार, घर के निवासियों पर यह भार होगा कि वे इस बात का ठोस स्पष्टीकरण दें कि अपराध कैसे किया गया। घर के निवासी केवल चुप रहकर और*

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

<u>कोई स्पष्टीकरण न देकर बच नहीं सकते, क्योंकि उनका मानना है कि अपना मामला साबित करने का भार पूरी तरह से अभियोजन पक्ष पर है और अभियुक्त पर कोई स्पष्टीकरण देने का कोई दायित्व नहीं है।</u>

इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों पर ध्यान दिया और रिपोर्ट के पैरा 31 से 34 में निम्नलिखित सिद्धांत निर्धारित किए: "31. यह प्राचीन नियम कि अभियुक्त के अपराध को साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है, एक पुराना सिद्धांत नहीं माना जाना चाहिए मानो यह किसी बुद्धिमान तर्क की प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करता। अनुमान का सिद्धांत उपरोक्त नियम से अलग नहीं है, न ही यह नियम के स्वभाव को ख़राब करेगा। दूसरी ओर, यदि अभियोजन पक्ष के सबूत के भार से संबंधित पारंपरिक नियम को पांडित्यपूर्ण कवरेज में लपेटने की अनुमति दी जाती है, तो गंभीर अपराधों के अपराधी प्रमुख लाभार्थी होंगे और समाज हताहत होगा।"

12.2. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित मामले में दिए गए निर्णय से भी अवगत है।**उमा और अन्य बनाम पुलिस उपाधीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया राज्य, (आपराधिक अपील संख्या 757/2015,*22 अक्टूबर, 2024 को निर्णय लिया गया)***जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आपराधिक मामले का फैसला करने में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 की प्रयोज्यता और दायरे के संबंध में न्यायशास्त्र निर्धारित करते हुए, सबूत के बोझ के संबंध में नियम इस प्रकार निर्धारित किया:

"24. त्रिमुख मारोती किरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य, [2006] अनुपूरक (7) एस.सी.आर. 156 के मामले में, इस न्यायालय ने बताया है कि जब किसी अपराध को घर की गोपनीयता में हुआ कहा जाता है, जहां अभियुक्त मौजूद

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

*था, तो दो महत्वपूर्ण परिणाम सामने आते हैं।**सबसे पहले, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित ऐसे मामले को साबित करने के लिए अपेक्षित प्रमाण का स्तर परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अन्य मामलों की तुलना में कमतर होता है। दूसरे, अपीलकर्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह मृतक की मृत्यु के कारणों को स्पष्ट करे।**इस अर्थ में, साक्ष्य का भार सीमित रूप से स्थानांतरित होता है। यदि वह चुप रहता है या गलत स्पष्टीकरण देता है, तो ऐसी प्रतिक्रिया परिस्थितियों की श्रृंखला में एक अतिरिक्त कड़ी बन जाएगी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने यह दायित्व नहीं निभाया है कि मृतक को लगी चोटें हत्या संबंधी नहीं थीं और न ही उनके द्वारा पहुँचाई गई थीं।"*

*पिछले कुछ वर्षों में दुल्हन के माता-पिता द्वारा दहेज या धन की माँग में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। अदालतों में अक्सर ऐसे मामले आते हैं जहाँ पति या ससुराल वाले माँग पूरी न होने पर दुल्हन की हत्या तक कर देते हैं। ये अपराध आमतौर पर घर के अंदर पूरी गोपनीयता के साथ किए जाते हैं और अभियोजन पक्ष के लिए सबूत पेश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वह अपराध का गवाह ही क्यों न हो, किसी अन्य परिवार के सदस्य के खिलाफ गवाही देने के लिए आगे नहीं आता। पड़ोसी, जिनके साक्ष्य कुछ मददगार हो सकते हैं, आमतौर पर अदालत में गवाही देने से हिचकिचाते हैं क्योंकि वे अलग-थलग रहना चाहते हैं और पड़ोस के परिवार को नाराज़ नहीं करना चाहते।**दुल्हन के माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्य अपराध स्थल से दूर होने के कारण, प्रत्यक्ष साक्ष्य देने की स्थिति में नहीं होते हैं जिससे वास्तविक अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सके, सिवाय धन या दहेज की माँग और दुल्हन को हुए उत्पीड़न के। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि गुप्त रूप से या घर के अंदर किया गया अपराध बिना सज़ा के छूट जाए।*

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

12.3 यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों से भी अवगत है***राजस्थान राज्य बनाम जग्गू राम (आपराधिक अपील संख्या 1133 वर्ष 2000),*** *04.01.2008 को निर्णय लिया गया) और****बीरेंद्र साव, शंकर साव, शिला देवी बनाम बिहार राज्य (आपराधिक अपील संख्या 7, 2003,*** *01.04.2007 को निर्णय लिया गया)*जिसमें माननीय न्यायालय ने अभियुक्त के आचरण पर निम्नलिखित रूप से प्रकाश डाला:

> *"मृतका के माता-पिता को उसके सिर पर लगी चोटों और परिणामस्वरूप हुई मृत्यु के बारे में न बताने का अभियुक्त और उसके परिवार के सदस्यों का आचरण और यह तथ्य कि माता-पिता को सूचित किए बिना या पुलिस को सूचना दिए बिना 30.3.1993 की तड़के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया ताकि वह शव का पोस्टमार्टम करवा सके, यह दिखाने के लिए काफी हद तक सही है कि अभियुक्त ने जानबूझकर यह कहानी गढ़ी थी कि शांति @ गोकुल मिर्गी से पीड़ित थी और दौरे के दौरान दरवाजे की छड़ से टकराने से उसके सिर पर चोटें आईं। शव को गुपचुप तरीके से निपटाने से स्पष्ट रूप से यह स्थापित होता है कि अभियुक्त ने शांति @ गोकुल की मृत्यु के वास्तविक कारण को छिपाने के एकमात्र उद्देश्य से ऐसा किया था। 19.हमारे विचार से, यह साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 को लागू करने के लिए एक उपयुक्त मामला था, जो यह निर्धारित करता है कि जब कोई तथ्य विशेष रूप से किसी व्यक्ति के ज्ञान में होता है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर होता है।"*

12.4. यह न्यायालय यह मानता है कि वर्तमान मामले में आरोपी प्रति वादियों ने पीड़िता की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्यों या पुलिस को सूचित किए बिना

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

जल्दबाजी में उसका अंतिम संस्कार कर दिया और इस प्रकार पोस्टमार्टम को भी रोक दिया। उसके मृत शरीर को ले जाने की घटना उनके आचरण को बयां करती है और कहानी गढ़ने और खुद को बचाने के लिए सबूतों को नष्ट करने की उनकी मंशा को प्रकट करती है।

12.5 यह न्यायालय आगे यह देखता है कि घटना आरोपी-प्रति वादियों के घर की चारदीवारी के भीतर हुई और पीड़िता की जलने से मौत की बात एक ऐसी परिस्थिति है जो विशेष रूप से आरोपी-प्रति वादियों के ज्ञान में है। इसके अलावा, वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने धारा 304-बी आईपीसी के आवश्यक तत्वों को साबित करके अपना प्रारंभिक भार पूरा कर लिया है, जिससे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत आरोपी-प्रति वादियों पर यह भार आ जाता है कि वे उन परिस्थितियों को स्पष्ट करें जिनमें यह घटना घटी। हालांकि, वर्तमान मामले में आरोपी-प्रतिवादी चुप रहे हैं और उन्होंने इस बिंदु पर कोई ठोस स्पष्टीकरण नहीं दिया है।

12.6. इस न्यायालय ने यह भी पाया कि नक्शा मौका (एक्स.पी. 4) के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि घटनास्थल पर जले हुए कपड़े, मिट्टी और एक खाली प्लास्टिक कंटेनर मिला था। इसके अलावा, घर में मिट्टी के तेल की गंध थी। यह न केवल अभियोजन पक्ष के मामले को मजबूत करता है, बल्कि आरोपी प्रति वादियों पर धारा 106 आईईए के आधार पर अपने घर में उपरोक्त की मौजूदगी को समझाने का भार भी डालता है, जो उनकी ओर से किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में मामले को उनके खिलाफ कर देता है।

12.7. इसलिए, यह न्यायालय तथ्यात्मक मैट्रिक्स और ऊपर उद्धृत मिसाल कानून के प्रकाश में यह पाता है कि वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष ने अपना प्रारंभिक भार

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

निर्वहन कर दिया है और इस प्रकार प्रश्नगत अपराध के आवश्यक तत्वों को साबित करके मामले को अपने पक्ष में कर लिया है और साथ ही, आरोपी-प्रतिवादी धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के आधार पर उन पर डाले गए भार का निर्वहन करने में विफल रहे हैं.

13. यह न्यायालय इस बात से अवगत है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप करने की शक्ति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 के अंतर्गत प्रदान की गई है, जिसके अनुसार, अपीलीय न्यायालय विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय को पलट सकता है और अभियुक्त को दोषी ठहराकर विधि के अनुसार दण्डित कर सकता है। धारा 386 का प्रासंगिक अंश नीचे प्रस्तुत है:-

> *"**386. अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ।***
>
> *—ऐसे अभिलेख का अवलोकन करने और अपीलकर्ता या उसके वकील को सुनने के पश्चात्, यदि वह उपस्थित होता है, और लोक अभियोजक को सुनने के पश्चात्, यदि वह उपस्थित होता है, और धारा 377 या धारा 378 के अधीन अपील की स्थिति में, अभियुक्त को सुनने के पश्चात्, यदि वह उपस्थित होता है, तो अपील न्यायालय, यदि वह समझता है कि हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, अपील को खारिज कर सकता है, या—*
>
> *(क) किसी आदेश या दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में, ऐसे आदेश को उलट सकता है और निर्देश दे सकता है कि आगे की जांच की जाए, या अभियुक्त पर पुनः मुकदमा चलाया जाए या उसे सुनवाई के लिए सौंपा जाए, जैसा भी मामला हो, या उसे दोषी पाकर कानून के अनुसार उस पर सजा सुना सकता है;"*

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

14. निम्नलिखित मामलों में***मल्लप्पा एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (आपराधिक अपील संख्या 1162/2011, 12.02.2024 को निर्णीत)*** और ***बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौदर एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य (आपराधिक अपील संख्या 985/2010, 19.04.2024 को निर्णीत),***माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

मल्लप्पा एवं अन्य (सुप्रा):

> *"36. हमारा आपराधिक न्यायशास्त्र मूलतः इस वचन पर आधारित है कि किसी भी निर्दोष को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। आपराधिक कानून के सभी सुरक्षा उपाय और न्यायशास्त्रीय मूल्य, न्याय की किसी भी विफलता को रोकने के लिए हैं। बरी होने की अपील पर निर्णय लेते समय जिन सिद्धांतों का पालन किया जाता है, उन्हें संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है:*
>
> *(i) साक्ष्य का मूल्यांकन आपराधिक मुकदमे का मुख्य तत्व है और ऐसा मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए जिसमें मौखिक या दस्तावेजी सभी साक्ष्य शामिल हों;*
>
> *(ii) साक्ष्य का आंशिक या चयनात्मक मूल्यांकन न्याय की विफलता का कारण बन सकता है और यह अपने आप में चुनौती का आधार है;*
>
> *(iii) यदि न्यायालय, साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद पाता है कि दो दृष्टिकोण संभव हैं, तो सामान्यतः अभियुक्त के पक्ष में दृष्टिकोण का ही अनुसरण किया जाएगा;*
>
> *(iv) यदि ट्रायल कोर्ट का दृष्टिकोण कानूनी रूप से प्रशंसनीय है, तो विपरीत दृष्टिकोण की संभावना मात्र से बरी करने के फैसले को पलटना उचित नहीं होगा;*
>
> *(v) यदि अपीलीय न्यायालय साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर अपील में दोषमुक्ति को पलटने के लिए इच्छुक है, तो उसे दोषमुक्ति के लिए ट्रायल*

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

कोर्ट द्वारा दिए गए सभी कारणों को विशेष रूप से संबोधित करना होगा और सभी तथ्यों को शामिल करना होगा;

(vi) दोषमुक्ति से दोषसिद्धि में उलटफेर के मामले में, अपीलीय न्यायालय को ट्रायल कोर्ट के निर्णय में अवैधता, विकृति या कानून या तथ्य की त्रुटि प्रदर्शित करनी होगी।"

बाबू साहेबगौड़ा रुद्रगौदर और अन्य (सुप्रा):

"39. इस प्रकार, यह संदेह से परे है कि अभियुक्त के पक्ष में ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के फैसले को पलटने के लिए अपीलीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का दायरा निम्नलिखित सिद्धांतों के चार कोनों के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए:

(क) दोषमुक्ति का निर्णय स्पष्ट रूप से विकृत है;

(ख) यह रिकॉर्ड पर मौजूद भौतिक साक्ष्य पर विचार करने में हुई चूक/गलत व्याख्या पर आधारित है;

(ग) कोई भी दो उचित विचार संभव नहीं हैं और केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप विचार ही रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से संभव है।"

15. यह न्यायालय यह मानता है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप की गुंजाइश पूर्वोक्त पूर्ववर्ती कानून के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 386 में भी प्रदान की गई है, और जब इसे वर्तमान मामले में लागू किया जाता है, तो यह पता चलता है कि दोषमुक्ति का विवादित निर्णय पारित करते समय विद्वान विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद भौतिक साक्ष्य को गलत पढ़ा था और गवाहों की गवाही और प्रदर्शित दस्तावेजों की व्याख्या में एक अति-तकनीकी दृष्टिकोण अपनाया है, जो सामाजिक कल्याण प्रावधानों से संबंधित मामलों में वांछनीय नहीं है, खासकर जब

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

दहेज हत्या का खतरा भारतीय समाज में गहराई से व्याप्त है। इसके अतिरिक्त, आरोपी प्रतिवादी उन परिस्थितियों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण देने में विफल रहे हैं जिनके तहत घटना घटी, जिससे वे धारा 106 आईईए के तहत दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहे। यह न्यायालय आगे यह भी मानता है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री के आधार पर, वर्तमान मामले में आरोपी प्रतिवादी (रामदीन और विद्यादेवी) को धारा 498-ए और 304-बी और 201 आईपीसी के तहत दोषी ठहराने के अलावा कोई अन्य दृष्टिकोण नहीं हो सकता था।

16. इस प्रकार, समग्र साक्ष्य और रिकॉर्ड पर सामग्री को देखते हुए, आरोपी-प्रति वादियों को धारा 498-ए, 304-बी, और 201 आईपीसी के तहत बरी करने का निर्णय कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है, और इसलिए, अपीलीय-राज्य द्वारा दायर वर्तमान अपील***अनुमत***, जबकि विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 11.04.2002 के बरी करने के विवादित फैसले को रद्द और अलग रखा गया।

16.1. परिणामस्वरूप, अभियुक्त-प्रति वादियों को नीचे उल्लिखित सजा दी जाती है:

धारा के तहत अपराध	**वाक्य**	**जुर्माना**
304-बी आई.पी.सी	7 वर्ष का साधारण कारावास (प्रत्येक)	-
498-ए आई.पी.सी	2 वर्ष का साधारण कारावास (प्रत्येक)	प्रत्येक को 2000/- रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)

201 आई.पी.सी	2 वर्ष का साधारण कारावास (प्रत्येक)	प्रत्येक को 1000/- रुपये का जुर्माना, अदा न करने पर 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

उपरोक्त सजाएँ एक साथ चलेंगी।

16.2. अभियुक्तगण जमानत पर हैं। उनके जमानत बांड निरस्त/जब्ती किए जाते हैं। उन्हें तत्काल वापस हिरासत में लेने तथा वर्तमान निर्णय द्वारा दी गई सजा काटने हेतु संबंधित जेल भेजने का आदेश दिया जाता है।

16.3. सभी लंबित आवेदनों का निपटारा किया जाता है। विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तत्काल वापस भेजा जाए।

(मदन गोपाल व्यास**),** जे **(**डॉ**.** पुष्पेन्द्र सिंह भाटी**),** जे

स्केंट /-

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाशा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निश्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"

Tarun Mehra
Advocate

(28/05/2025 को सुबह 08:55:04 बजे डाउनलोड किया गया)